उत्तराखण्ड सरकार
सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड़, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com Website : www.uttarainformation.gov.in टेलीफैक्स 0135–2711069

देहरादून 29 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–05(12/139)

गुरूवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सचिवालय में मुंशी हरि प्रसाद टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान, गरूड़ाबाज अल्मोड़ा की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने संस्थान के निर्माण कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य में परम्परागत शिल्प एवं शिल्पियों को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के लिए सबसे पहले मास्टर ट्रेनर तैयार कर स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसके लिए प्रशिक्षुओं को हाईलेवल सर्टिफिकेट भी प्रदान किये जाएं। उन्होंने कहा कि शिल्पियों को उद्यमी के रूप में स्थापित करना इस संस्थान का उद्देश्य होना चाहिए।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य के शिल्पियों को रजिस्टर किया जाना आवश्यक है। शिल्पियों का रजिस्ट्रेशन किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य की परम्परागत शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए मास्टरक्राफ्टमैन तैयार किये जाएं। इसके लिए प्रशिक्षण आदि की विधियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही उन्नत टूल किट्स आदि के विकास पर भी ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा संस्थान के भवन से ज्यादा उसके कम्पोनेंट्स पर ध्यान दिया जाए। शिल्प कला को नई तकनीक से जोड़कर उन्नत बनाया जाए।

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि संस्थान की कार्यकारिणी में जिलाधिकारी अल्मोड़ा को भी शामिल किया जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि संस्थान को निश्चित समय सीमा के अन्दर तैयार कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार गरूड़ाबाज को मॉडल टाऊन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है।

इस अवसर पर बताया गया कि संस्थान के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है एवं संस्थान हेतु चयनित भूमि में बाउण्ड्रीवॉल, गेट एवं रोड आदि का कार्य 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है।

इस अवसर पर मुंशी हरि प्रसाद टम्टा परम्परागत शिल्प उन्नयन संस्थान की प्रबन्ध कार्यकारिणी के अध्यक्ष चनर राम आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) एवं अन्य सदस्य उपस्थित थे।

देहरादून 29 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–04(12/138)

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के ससुर मेजर(से.नि.) जगदीश प्रसाद कुकरेती के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने दिवंगत की आत्मा की शांति और दुःख की इस घड़ी में स्व. कुकरेती के परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की।

एम.पी. कैलखुर, ओ.एस.डी., सूचना : 7055007010

देहरादून 29 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(12/137)

सचिव सूचना विनोद शर्मा ने बताया है कि प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के माध्यम से रोजगार, पर्यटन के महत्व को बढ़ाने एवं क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करने, निजी क्षेत्र से पूँजी निवेश को आकर्षक बनाने के लिए उत्तराखण्ड फिल्म नीति में प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पडे सिनेमाहॉलों को पुनर्जीवित किये जाने हेतु प्रदेश के 1000 मीटर से ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में बन्द पड़े सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करते हुए आगामी 05 वर्षों के लिए मनोरंजन कर से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 29 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–02(12/136)

मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गुरूवार को रायपुर देहरादून में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा में भाग लेने के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु विकास योजनाएं संचालित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की सामाजिक पेंशन समाज के प्रत्येक कमजोर वर्ग को प्रदान की जा रही है। दो साल पहले तक राज्य में सामाजिक पेंशनो को प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या 1.84 लाख थी जो अब 7 लाख से ऊपर हो गयी है। राज्य सरकार का लक्ष्य इन पेशंन लाभार्थियों की संख्या 10 लाख तक करने का है। पहले मात्र 1000 रूपये की आमदनी वाला व्यक्ति पेंशन का पात्र था लेकिन राज्य सरकार ने आय सीमा को बढ़ाकर अब 4000 रूपये कर दिया है। देश में अन्य कोई ऐसा राज्य नही है जो अपनी जनता को इतनी प्रकार की पेंशन प्रदान करता हो। विकलांग, बौने, जागरी, मौलवी, विक्षिप्त व्यक्ति की पत्नी, जन्म के समय विकलांग होने वाले बच्चे, विधवा, परित्यकता आदि विभिन्न प्रकार की पेंशन राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। वास्तव में राज्य सरकार इन पेंशनों के माध्यम से राज्य के कमजोर व असहाय जनता में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करता चाहती है ताकि वह किसी भी परिस्थिती में स्वयं को अकेला अनुभव न करे। जनता को यह विश्वास रहे कि राज्य सरकार उनके साथ एक मददगार की तरह उनके साथ है।

उत्तराखण्ड पूरे देश में तमिलनाडु के बाद दूसरा एकमात्र राज्य बन गया है जिसकी 90 प्रतिशत जनसंख्या अन्न सुरक्षा पा रही है। उत्तराखण्ड के समाज का कोई भी कमजोर हिस्सा ऐसा नही है जिसे राज्य सरकार द्वारा पेंशन के रूप में कोई आर्थिक सहायता नही दी जा रही हो । राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है कि सामाजिक पेंशन पाने वाले लाभार्थियों की संख्या 10 लाख तक की जायेगी।

मुख्यंमत्री श्री रावत ने उपस्थित महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि हम मातृ शक्ति का सम्मान करते है। आज राज्य सरकार जन्म से वृद्धावस्था तक प्रत्येक स्तर पर उनके साथ है। राज्य सरकार कन्या जन्म पर निर्धन परिवारों को 5000 रूपये प्रदान करती है। बालिकाओं की शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए गौरादेवी योजना संचालित है। लड़कियों के विवाह के अवसर पर नन्दा देवी योजना के अर्न्तगत निर्धन वर्ग की लड़कियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। गर्भावस्था में उनकों पौष्टिक अनाज व अन्य सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है इनमें आंगनबाड़ियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। वृद्ध महिलाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गयी है साथ ही मेरे बुर्जुग मेरे तीर्थ योजना के अर्न्तगत उन्हें चारधाम यात्रा निःशुल्क करवायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा कमजोर बच्चों को आंगनबाडी के माध्यम से पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से अनुरोध किया कि कमजोर बच्चों को आंगनबाड़ी में ले जाया जाय। महिलाओं को 5 रूपये प्रति लीटर बोनस प्रदान किया जा रहा है। निर्धन विधवा महिलाओं को गंगा गाय योजना के अर्न्तगत गाय प्रदान की जा रही है। इन्दिरा अम्मा भोजनालय योजना महिलाओं के लिए संचालित की गयी है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्थानीय उत्पादों को बेचने के प्रयासो को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों व महिला मंगल दलों से प्राप्त स्थानीय उत्पादों की बिक्री से जितनी भी आय प्राप्त करेगी उसका 5 प्रतिशत महिला मंगल दलो व स्वय सहायता समूहों को दिया जायेगा। 5000 रूपये की आरम्भिक राशि से महिला मंगल दलों के खाते खोले जायेगे। व्यवसायिक गतिविधियॉ आरम्भ करने के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को 20 से 25 हजार तक का अनुदान प्रदान किया जायेगा। आर्थिक स्वालम्बन ही महिला सशक्तीकरण की कुंजी है। राज्य सरकार विश्वास करती है कि अब नारी शक्ति ही उत्तराखण्ड के विकास के द्वार खोलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सराकर राज्य में महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है। राज्य में महिला उद्यमिता के विकास, महिला मंगल दला तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस वर्ष पुलिस में

महिला कॉस्टेबल की 1000 तथा सब इंसपेक्टर की 200 भर्तियॉ कि गयी। होमगार्ड व पीआरडी में 30 प्रतिशत महिलाऐ भर्ती की जायेगी। राज्य सरकार 2017 से पहले सरकार के चार विभागों में सिर्फ महिलाओं की भर्ती सुनिश्चित करेगी।

उत्तराखण्ड की जनता, कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिधि तथा मंत्रीगण बधाई के पात्र है जिनके प्रयासों से 2013 की आपदा जैसी भयकर तबाही के बाद भी आज राज्य सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में अग्रणी है। हम खुशहाल, प्रगतिशील व विकसित उत्तराखण्ड बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि यह उत्तराखण्ड की जनता के परिश्रम का ही फल है कि 2013 की भयंकर त्रासदी के बाद जिसमे राज्य का 60 प्रतिशत भाग तबाह हो गया आज सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर है। विभिन्न स्वंत्रत संस्थाओं व अर्न्तराष्ट्रीय संगठनों के अध्ययन से यह परिणाम निकले है। नीति आयोग ने कहा है कि देश के ऐसे 6 राज्य जो 12 प्रतिशत से अधिक वृद्धिदर से विकास कर रहे है उनमें उत्तराखण्ड का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व बैंक ने घोषित किया है कि भारत में उत्तराखण्ड राज्य में उद्योग व व्यवसायिक गतिविधियों के लिए अनुकूल व अच्छा वातावरण है तथा इस सन्दर्भ में उत्तराखण्ड का स्थान प्रथम है। हाल ही में ऐसाचैम ने कहा कि उत्तराखण्ड तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में अग्रणी है।

देहरादून 29 दिसम्बर, 2016(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(12/135)**

प्रदेश के 500 विद्यालयों में बूट (BOOT) मॉडल में आईसीटी (इन्फार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी) योजना संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत ने इसके प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार ने बताया है कि केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत राज्य के 500 विद्यालयों में बूट(BOOT) मॉडल में आईसीटी योजना संचालित करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अतर्गत तैयार किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसमें राज्य की आवश्यकताओं व भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक विशिष्टियां शामिल की गई हैं। इससे राज्य के कुल 500 विद्यालयों के लगभग 1 लाख 90 हजार बच्चे लाभान्वित है।

रवि बिजारनियां, सहायक निदेशक : 7055007012